URGENT
PARLIAMENTARY COMMITTEE MATTER

F . No. 15011/31/2021-SC/ST-W
Ministry of Home Affairs
Government of India
Women Safety Division.
****

2nd Floor, MDC National Stadium,
New Delhi – 110001,
Date :15.11.2021.

To

1. The Addl. Chief Secretaries/Pr. Secretary (Home)/Home Secretaries of all States/UTs.
2. The Directors General of Police of all States/UTs.

Subject: Strengthening Capacity to deal with cases of crimes against Women-Reg.

Reference:
1. Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/126/2020-SC/ST-W dated 30.06.2021.
2. Standard Operating Procedure (SOP) for Investigation and Prosecution of Rape against Women issued by BPR&D and circulated by Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/126/2020-SC/ST-W dated 19.05.2021.
3. Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/190/2020-SC/ST-W dated 09.10.2020.
4. Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/126/2020-SC/ST-W dated 29.07.2020.
5. Ministry of Home Affairs' D.O. letter no. 1(8)/2018-WS-IV(CCTNS) dated 05.12.2019.
6. Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/75/2019-SC/ST-W dated 16.05.2019.
7. Ministry of Home Affairs Advisory no. 22011/05/2010-SR (CCTNS) dated 30.11.2015.
8. Ministry of Home Affairs Advisory no. 15011/35/2013-SC/ST-W dated 10.05.2013.

Madam/Sir,

I am directed to draw your kind attention to the above mentioned advisories and SOP issued by Ministry of Home Affairs for strengthening capacity to deal with cases of Crimes against Women and to say that Department Related Parliamentary Standing Committee on Home affairs in its 233rd Report has given several recommendations on strengthening the mechanism for dealing with crimes against Women, specially SOPs on registration of FIRs including details on total Zero FIRs filed & disposed and training to Police Personnel on dealing with crimes against Women using BPR&D's SOP.

...2/-

2. The Standing Committee has also recommended that SOPs on registration of FIRs should include guidelines to Police to record reasons for delay in reporting of crime by the Complainants to the Police. It is stated that this field is provided in the CCTNS in IIF-1 (copy enclosed). The States/UTs may also widely circulate the BPR&D's Handbook on "Women's Safety & Security. A handbook for First Respondents and Investigators in the Police to all its personnel, as well as include them in the training modules.

3. In this context, attention is also invited to the use of Crime Analytics by Delhi Police in prevention of street crimes through crime mapping and Identification of hot spots for reinforced action. The Parliamentary Standing Committee has recommended that similar efforts may be taken in other metropolitan cities. In doing so , the Crime Mapping Analytics and Productive system (CMAP) and COGNOS BI tool deployed on CCTNS may be utilized. These have been made available to States/UTs by National Crime Records Bureau.

4. Considering that the Parliamentary Standing Committee has sought a Status Note on the above, it is requested that suitable direction may be issued for early commencement of action in the matter and continuous monitoring of the implementation at ground level may be undertaken regularly to calibrate the action.

(Pawan Mehta)
Deputy Secretary to the Govt of India
Tele No. 23075293

Copy for information to:

1. **The Director,**
   National Crime Records Bureau,
   NH-8, Mahipalpur, New Delhi.

2. **Director General,**
   Bureau of Police Research & Development,
   NH-8, Mahipalpur, New Delhi.

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. District........................P.S. .... Year.............. FIR No. .... Date...................

2. (i) Act .... Sections ....

   (ii) Act .... Sections...

   (iii) Act .... Sections ....

   (iv) Other Acts & Sections ....

3. (a) Occurrence of offence: Day................... Date from..................... Date to.........................

   Time Period .... Time from..................... Time to............................

   (b) Information received at P.S.: Date .... Time ....

   (c) General Diary Reference : Entry No. .... Time ....

4. Type of Information : Written / Oral

5. Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P.S. ....

   .... Beat No. ....

   (b) Address...

   ....

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then

   Name of P.S. .... District ....

6. Complainant / Informant :

   (a) Name ....

   (b) Father's/Husband's Name ....

   (c) Date/Year of Birth .... (d) Nationality ....

   (e) Passport No. .... Date of Issue .... Place of Issue ....

   (f) Occupation ....

   (g) Address ....

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:
   (Attach separate sheet, if necessary)

   (1) ....

   (2) ....

   (3) ....

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant

   ....

   ....

9. Particulars of properties stolen (Attach separate sheet, if necessary)

   ....

   ....

10. Total value of property stolen ....

11. Inquest Report / U.D. case No., if any ....

12. First Information contents (Attach separate sheet, if required):

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. :
(1) Registered the case and took up the investigation or

(2) Directed (Name of I.O.) .... Rank .... No. .... to take up the Investigation or

(3) Refused investigation due to .... or

(4) Transferred to P.S. .... District .... on point of jurisdiction.

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

R.O.A.C.

Signature of Officer in charge, Police Station

Name ....

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant.

Rank..................................... **No.** ....

15. Date and time of despatch to the court ....

Attachment to item 7 of First Information Report

तत्काल
संसदीय समिति मामला

फा.सं. 15011/31/2021-एससी/एसटी-डब्ल्यू
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
महिला सुरक्षा प्रभाग
****

दूसरा तल, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,
नई दिल्ली-110001
दिनांक..15.11.2021

सेवा में
1. सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह)/गृह सचिव
2. सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक।

विषय: महिलाओं के प्रति आपराधिक मामलों से निपटने की क्षमता बढ़ाए जाने के बारे में।

संदर्भ: 1. गृह मंत्रालय की दिनांक 30.06.2021 की एडवाइजरी संख्या 15011/126/2020-एससी/एसटी-डब्ल्यू
2.महिलाओं के बलात्कार संबंधी मामलों की जांच और अभियोजन के लिए बीपीआरएंडडी द्वारा जारी की गई तथा गृह मंत्रालय की दिनांक 19.05.2021 की एडवाइजरी संख्या 15011/126/2020-एससी/एसटी-डब्ल्यू के तहत परिचालित की गई मानक संचालन प्रक्रिया
3. गृह मंत्रालय की दिनांक 09.10.2020 की एडवाइजरी संख्या 15011/190/2020-एससी/एसटी-डब्ल्यू
4.गृह मंत्रालय की दिनांक 29.07.2020 की एडवाइजरी संख्या 15011/126/2020-एससी/एसटी-डब्ल्यू
5.गृह मंत्रालय का दिनांक 05.12.2019का अ.शा. पत्र सं. 1(8)/2018-डब्ल्यूएस-IV (सीसीटीएनएस)
6. गृह मंत्रालय की दिनांक 16.05.2019 की एडवाइजरी संख्या 15011/75/2019-एससी/एसटी-डब्ल्यू
7.गृह मंत्रालय की दिनांक 30.11.2015 की एडवाइजरी संख्या 22011/05/2010-एसआर (सीसीटीएनएस)
8.गृह मंत्रालय की दिनांक 10.05.2013 की एडवाइजरी संख्या 15011/35/2013-एससी/एसटी-डब्ल्यू

महोदया/महोदय,

मुझे, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त एडवाइजरी तथा मानक संचालन प्रक्रिया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 233वीं रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने वाले तंत्र की मजबूती के लिए अनेक सिफारिशें जारी की हैं जिनमें विशेषकर दायर और निपटाई गईं कुल जीरो एफआईआर के विवरण सहित एफआईआर के पंजीकरण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से

...2/-

निपटने के लिए बीपीआरएंडडी द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

2. स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एफआईआर के पंजीकरण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को अपराध की सूचना दिए जाने में हुए विलम्ब के कारण को भी दर्ज किए जाने संबंधी पुलिस के लिए दिशानिर्देशों को भी शामिल किया जाए। यह उल्लेख किया जाता है कि इस फील्ड का सीसीटीएनएस के आईआईएफ-I (प्रति संलग्न) में भी प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा "वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी" संबंधी बीपीआरएंडडी की हैंडबुक का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। पुलिस के प्रथम कार्रवाईकर्ताओं तथा जांचकर्ताओं के लिए हैंडबुक को, सभी कार्मिकों को प्रदान किया जाना चाहिए और इसे उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी शामिल किया जाना चाहिए।

3. इस संदर्भ में, ठोस कार्रवाई के लिए क्राइम मैपिंग तथा हॉटस्पॉट की पहचान करके गलियों में होने वाले अपराधों की रोकथाम में दिल्ली पुलिस द्वारा क्राइम एनालिटिक्स के प्रयोग की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। संसदीय स्थायी समिति ने अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाने की सिफारिश की है। ऐसा करके, क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रोडक्टिव सिस्टम (सीएमएपी) तथा सीसीटीएनएस पर लगाए गए सीओजीएनओएस बीआई टूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ये टूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

4. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसदीय स्थायी समिति ने उपर्युक्त के संबंध में एक स्थितिपरक नोट की मांग की है, यह अनुरोध किया जाता है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए तथा कार्रवाई के आकलन के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जाए।

(पवन मेहता)
उप-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23075293

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

1. **निदेशक,**
   राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,
   राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली।

2. **महानिदेशक,**
   पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो,
   राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली।